विचार बिन्दु

कर्मों की आवाज़ शब्दों से ऊंची होती है। –कहावत

चिकित्सा सेवाएं वेंटिलेटर पर!

राजस्थान में (ये पंक्तियां लिखी जाने तक) ज़ारी निजी अस्पतालों की हड़ताल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा केवल इलाज का साधन नहीं, बल्कि समय-समय पर आयोजित होने वाला एक सामूहिक नाटक भी है। एक ऐसा नाटक जिसमें किरदार तय हैं, संवाद तय हैं, और अंत भी लगभग तय ही होता है। फर्क बस इतना है कि इस नाटक का टिकट हमेशा मरीज को ही खरीदना पड़ता है, और वह भी अपनी जेब से नहीं, अपने धैर्य और कभी-कभी अपनी जान से भी।

जयपुर में एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई। उन पर गम्भीर आर्थिक अनियमितता का आरोप था। डॉक्टरों के संगठित समूह को बुरा लगा। यह स्वाभाविक है। आखिर आत्मसम्मान कोई मामूली चीज तो है नहीं, जिसे पुलिस की जीप में बैठाकर ले जाया जा सके। सो, आत्मसम्मान की रक्षा का सबसे उपयुक्त तरीका खोजा गया। खोजने की भी ज़रूरत नहीं थी। पता ही था। उसे ही काम में लिया गया। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है! मरीजों को समझना चाहिए कि डॉक्टर भी इंसान हैं, केवल अलबर्टपिण्टो को ही नहीं उन्हें भी गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो बतर्ज़ तबेले की बला बंदर के सर, गुस्से का शिकार मरीज़ को होना पड़ता है। सो हो रहे हैं! उधर सरकार भी कम दिलचस्प नहीं है। उसे भी लगा कि कानून का राज स्थापित करना जरूरी है। और कानून का राज स्थापित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? एक डॉक्टर को इस तरह गिरफ्तार किया जाए कि बाकी डॉक्टरों को यह स्पष्ट संदेश मिल जाए कि सत्ता किसकी है। संवाद, समझाइश, या पेशेवर मर्यादा वगैरह ये सब किताबों में अच्छे लगते हैं, जमीनी हकीकत में नहीं।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प किंतु दयनीय पात्र है जनता या कहें मरीज़। वह हर दृश्य में मौजूद है, लेकिन उसकी कोई संवाद-रेखा नहीं है। वह बस इधर-उधर भागता है, लाइन में खड़ा होता है, दरवाजों से धकियाया या लौटाया जाता है, और अंत में यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी? शायद यही कि उसने बीमार पड़ने की गुस्ताख़ी कैसे की? वह भी ऐसे समय में जब डॉक्टरों और सरकार के बीच गरिमा बनाम कानून का महामुकाबला चल रहा था। और वैसे सरकार ने अपना फ़र्ज भी बखूबी निभाया। उसने घोषणा की कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु चल रही हैं। कुछ छोटी-मोटी नुमाइशी गतिविधियां भी उसने की, ताकि हम विश्वास कर सकें कि वह हमारे लिए फिक्रमंद है!

हड़ताल के कारण राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल, जयपुर का सवाई मान सिंह अस्पताल में ऐसा लग रहा था मानो कोई मेला लगा हो! फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ झूले नहीं, स्ट्रेचर थे; और मिठाइयों की जगह दवाइयों की पर्चियाँ बंट रही थीं। बंट क्या रही थीं, उनके लिए छीना झपटी चल रही थी। जो लोग कभी इस अस्पताल की भीड़ को व्यवस्था की विफलता मानते थे, उन्होंने उस दिन जाना कि विफलता भी एक सापेक्ष शब्द है-क्योंकि इससे बदतर भी कुछ हो सकता है। हो रहा था। दूसरी तरफ अलग ही दृश्य था। जहाँ आम दिनों में निजी अस्पतालों के बाहर पार्किंग तक न मिलती थी, वहाँ हड़ताल के चलते ऐसा सन्नाटा था मानो किसी जादुई छड़ी के घूमने से पूरा शहर स्वस्थ हो गया है। वैसे, यह सन्नाटा केवल इमारतों में नहीं था, बल्कि उस भरोसे में भी था, जो मरीज इन संस्थानों पर करता है।

उधर सोशल मीडिया पर अलग ही माहौल था। कुछ लोग निजी अस्पतालों को खुले आम लूट केंद्र घोषित कर रहे थे तो जवाबी हमले के रूप में कहा जा रहा था कि तुम वहां जाते ही क्यों हो? आखिर सरकार ने इतने सारे अस्पताल खोल रखे हैं, उनकी सेवाओं का लाभ क्यों नहीं लेते? इस भाषिक युद्ध में किसी को इतना याद कर लेने की ज़रूरत नहीं थी कि सरकारी सेवाएं न केवल अपर्याप्त हैं (ऊंट के मुंह में जीरा याद है किसी को?) सच तो यह है कि सरकार उनको बेहतर बनाने की बजाय ख़ुद निजी चिकित्सा सेवाओं को प्रोत्साहित करने में लगी हैं। सरकारों ने बग़ैर कहे यह कह दिया है कि नागरिक का स्वास्थ्य उसकी चिंता का विषय नहीं है। मुसाफ़िर अपने जान-माल की रक्षा ख़ुद करे! सरकारी अस्पताल बदहाली का नमूना बनते जा रहे हैं। न सुविधाएं हैं, न स्टाफ़ और न बजट! बजट लगातार कम किया जा रहा है। बेचारा मरीज़ निजी अस्पतालों में न जाए तो क्या करे?

अस्पतालों की हड़ताल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा केवल इलाज का साधन नहीं, बल्कि समय-समय पर आयोजित होने वाला एक सामूहिक नाटक भी है। एक ऐसा नाटक जिसमें किरदार तय हैं, संवाद तय हैं, और अंत भी लगभग तय ही होता है। फर्क बस इतना है कि इस नाटक का टिकट हमेशा मरीज को ही खरीदना पड़ता है, और वह भी अपनी जेब से नहीं, अपने धैर्य और कभी-कभी अपनी जान से भी।

राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी जिसे सरकारी सेवा वालों और सेवा निवृत्त मरीजों (तथा कुछ और लोगों) की सुविधा के लिए बनाया गया था, अब खुद इतनी बीमार लगती है कि उसका इलाज कौन करेगा, यह तय नहीं हो पा रहा। यहीं यह कह देना ज़रूरी है कि यह सेवा सरकार की कृपा नहीं है। वही कृपा जिसे आजकल फ्रीबीज़ कहकर गरियाए जाने का नया फ़ैशन चला है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के पैसों से यह योजना संचालित होती है। सरकार का काम केवल इसके प्रबंधन का है। शुरू-शुरू में यह योजना अच्छी तरह चली, इससे लोगों को राहत मिली लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पटरी से उतरती गई। इसमें दोष किसी एक का नहीं, सभी का रहा। मरीज़ों ने इस सुविधा का कई तरह से दुरुपयोग किया, तो निजी अस्पतालों और डॉक्टरों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने से परहेज़ नहीं किया। एक बहुत बड़ी गड़बड़ प्राय: यह होने लगी कि सरकार की तरफ से अस्पतालों को भुगतान में बहुत देरी की जाने लगी। इस बार भी निजी अस्पतालों की एक शिकायत यह है कि उन्हें नौ-दस महीनों से भुगतान नहीं मिला है। यह शिकायत थोड़े-थोड़े दिनों में उभरती रहती है और सरकार है कि सरक-सरक कर चलना अपना धर्म माने बैठी है। मुझ जैसे अज्ञानियों के लिए यह पहली अबूझ है कि आखिर अस्पतालों को समय पर भुगतान क्यों नहीं किया जाता, और क्यों नहीं किया जा सकता है! क्या इस बात की किसी को परवाह है कि वर्तमान और भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? वह भी तब जब कि वे इस सेवा के लिए अग्रिम भुगतान कर चुके हैं।

अभी हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों का तर्क है कि उनकी गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर किसी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगे तो क्या डॉक्टरों के संगठन का एकजुट होकर इसके पक्ष में आंदोलित होना तर्क संगत कहा जाएगा? उनसे भी एक छोटा-सा प्रश्न तो किया ही जाना चाहिए। क्या मरीज की जिंदगी से समझौता किया जा सकता है? उनकी लड़ाई सरकार से है या मरीज़ से? या फिर उन्होंने तो यह मान लिया है कि गरिमा और जीवन के बीच यदि चुनाव करना पड़े, तो गरिमा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? इस हड़ताल ने हमें यह भी बता दिया है कि निजी अस्पताल अब केवल इलाज के केंद्र नहीं, बल्कि व्यवस्था को 'पॉज़' करने वाले बटन बन चुके हैं। एक दिन के लिए सेवाएं बंद करो, और पूरा शहर रुक जाता है। सरकारी अस्पतालों में भीड़ इस तरह उमड़ती है, मानो किसी ने अचानक घोषणा कर दी हो कि आज सभी सेवाएं मुफ्त हैं! भले ही यह 'मुफ्त' केवल कागजों में ही क्यों न हो! सरकार ने हमेशा की तरह स्थिति पर 'नज़र बनाए रखी' है। जैसे अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में रखी कोई पुरानी वस्तु, जिसे देखा तो जाता है, पर छुआ नहीं जाता। यह 'नज़र' बहुत कुछ देखती है, लेकिन बहुत कम करती है। और जब तक कुछ किया जाता है, तब तक अक्सर बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है।

यह पूरा घटनाक्रम हमें एक असहज करने वाली सच्चाई के सामने ला खड़ा करता है-क्या स्वास्थ्य सेवा अब भी सेवा रह गई है, या वह पूरी तरह से एक उद्योग, एक शक्ति संरचना और एक सौदेबाजी का मंच बन चुकी है? यदि एक डॉक्टर की गिरफ्तारी पूरे राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को ठप कर सकती है, तो यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक संकेत है कि व्यवस्था का संतुलन कहीं न कहीं बहुत गंभीर रूप से बिगड़ चुका है।

अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? शायद एक बैठक होगी, कुछ आश्वासन दिए जाएंगे, हड़ताल खत्म हो जाएगी, और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मरीज फिर से अस्पतालों में जाने लगेंगे, डॉक्टर फिर से इलाज करने लगेंगे, और सरकार फिर से अपनी फाइलों में व्यस्त हो जाएगी। और हम सब मिलकर राहत की सांस लेंगे। लेकिन कब तक? जब तक अगला संकट न आ जाए। यथार्थ यह है कि असली समस्या का समाधान करना हमारे सिस्टम की प्राथमिकता कभी रहा ही नहीं। स्थिति को किसी तरह संभाल लेना, उसे टाल देना, और फिर भूल जाना- हमारी प्राथमिकता तो यह रही है। राजस्थान की यह हड़ताल भी शायद कुछ दिनों बाद एक खबर बनकर रह जाएगी। ज़िंदगी फिर से अपने ढर्रे पर चलने लगेगी। हम में से अधिकांश इन असुविधाओं को विस्मृत कर देंगे। सिवा उनके जिन्होंने इस हड़ताल की वजह से अपने किसी प्रियजन को खो दिया होगा। लेकिन जो सवाल इसने उठाए हैं, वे यहीं रहेंगे। चुपचाप, अनुत्तरित, और अगले विस्फोट का इंतजार करते हुए।

और तब तक, मरीजों से बस यही अपेक्षा है कि वे धैर्य रखें, समझदारी दिखाएं, और सबसे जरूरी बात यह कि बीमार पड़ने से बचें। क्योंकि इस देश में बीमार पड़ना अब केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक और सामाजिक जोखिम भी है।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

उदयपुर के डेरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना

अभी तक की यात्रा से संबंधित जानने योग्य महत्वपूर्ण पहलू

वीर बहादुर सिंह

कृषि से सम्बंधित उदयपुर के महाविद्यालयों में मतस्य विज्ञान महाविद्यालय को छोड़कर डेरी विज्ञान महाविद्यालय को अपेक्षा कृत नवीन कह सकते हैं, परन्तु वो भी अब इतना नवीन नहीं रहा क्योंकि इसे स्थापित हुए अब लगभग 48 वर्ष हो चुके हैं। इसमें खाद्य प्रौद्योगिकी प्रोग्राम वर्ष 1998 में जोड़ा गया जिसकी अनुशंसा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतगत प्रदेश सरकार को मिली विदेशी सहायता के खर्च के आयामों पर पेश की गयी रिपोर्ट में की गई थी। डेरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी की वर्तमान बिल्डिंग इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई, और चार वर्ष का खाद्य प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्यक्रम अनुभवी वैज्ञानिकों यथा डॉ पार्पिया, डॉ प्रूथी, डॉ वानखेड़े, डिफेन्स फ़ूड रिसर्च लैब मैसूर के निदेशक के अलावा पंतनगर, लुधिअना, हिसार, आनंद आदि ने तीन दिन तक सम्बाद करके बनाया जिसे विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति ने अनुमोदित किया। इस प्रकार यह खाद्य प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्यक्रम डेरी के पाठ्यक्रम के समानांतर आरम्भ हुआ था।

डेरी विज्ञान महाविद्यालय की शुरुआत 1978 में हो गई थी। राजस्थान कृषि महाविद्यालय में डेरी विज्ञान विभाग हुआ करता था जिसके अंतर्गत डेरी विज्ञान के स्नातकोत्तर विषय और कृषि स्नातक के डेरी विषय पढ़ाये जाते थे। दोनों पाठ्यक्रमों के लिए वांछित फैकल्टी भी सदैव उपलब्ध रही। डेरी विज्ञान महाविद्यालय बनते ही कृषि संकाय का तत्कालीन डेरी विभाग डेरी कॉलेज से सम्बन्ध हो गया और सभी स्टाफ, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी आदि डेरी विज्ञान महाविद्यालय के अधीन हो गए।

यहाँ बताते चलें कि डेरी विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम की अनुशंसा राज्य सरकार पहले ही कर चुकी थी लेकिन किन्ही कारणों से तत्कालीन विश्वविद्यालय इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सका। फिर डेरी विकास के अंतर्गत प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड 1 और ऑपरेशन फ्लड 2 के अंतर्गत प्रदेश में बड़े पैमाने पर संगठनात्मक और संरचनात्मक कार्य आरम्भ हो चुका था। इसलिए यही समय अधिक उपयुक्त होते हुए डेरी विज्ञान की स्नातक शिक्षा को आरम्भ करने का प्लान बनाया गया ताकि नए स्थापित संयंत्रों को संचालित करने के लिए उपयुक्त टेक्निकल मैनपावर मिल सके। फलस्वरूप इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमे प्रदेश के बाहर से भी डेरी वैज्ञानिक और अनुभवी शिक्षक मौजूद थे। मैं उस समय जोबनेर स्थित कृषि महाविद्यालय में डेरी विज्ञान विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत था। वर्कशॉप से आमंत्रण के लिए मैनें भी उदयपुर आकर दो दिन मीटिंग में भाग लिया। तत्कालीन डीन कृषि अभियांत्रकी डॉ के.एन. नाग उस समय इस प्रोग्राम को अपने कॉलेज में ले जाने को प्रयासरत थे लेकिन डॉ रावत और डीन गुजरात के आनंद स्तिथ महाविध्यलाय के डीन ने इसके विपरीत प्रस्ताव रखे कियोंकि यह माना गया कि अलग कॉलेज से ही विषय और उसके विस्तार व् अनुसन्धान को सही दिशा मिलेगी। संवाद के दूसरे दिन समाप्ति पर।

डॉ. एन.आर. भसीन जो वर्क शॉप में मौजूद थे और वे राजस्थान के उभरते डेरी परिदृश्य के जनक तो थे ही, भविष्य की योजनाओं का खाका भी उनके दिमाग में बन चुका था, ने संवाद को समाप्त करते हुए अपना निर्णय दिया कि फिलहाल डेरी विज्ञान स्नातक की पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में की जाए और शनैः शनैः इस पाठ्यक्रम को आधार मानते हुए अन्य महाविद्यालयों की भांति एक डेरी विज्ञान का अलग महाविद्यालय शीघ्र बनाया जाय। डॉ नाग की मंशा पूर्ण होती न देख उनके अनुयायी खफा हो गए जो डेरी का कॉलेज बनने के उपरान्त भी खफा बने रहे। यद्यपि अभियंत्रकी महाविद्यालय से कई टीचर डेरी कॉलेज में इंजीनियरिंग से सम्बंधित कोर्स पढानें आते रहे और वह सिलसिला वर्तमान में भी इंटीग्रेटेड टीचिंग पध्यति के कारण चालू है।

बाद में डॉ नाग बीकानेर में स्थापित कृषि विश्व विध्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। लेखक भी वर्ष 1990 जुलाई में डेरी का अधिष्ठाता नियुक्त होकर जोबनेर से उदयपुर स्थानांतर हो गया। लेखक को उदयपुर कार्य करते ऐसे अनुभव भी हुए जिससे इस बात को बल मिला कि अभी भी असंतुष्ट वर्ग अलग डेरी कॉलेज बनने का दंश मन में पाले हुए हैं।

लेखक ने मैत्रयी भाव से तब इंजीनियरिंग कॉलेज के कई अध्यापकों से घनिष्ट सम्बन्ध बना लिए और डेरी कॉलेज के लिए उनका सहयोग सदैव मिलता रहा। परन्तु कतिपय वरिष्ठम टीचर्स मन में द्वेष पाले रहे और धरातल पर उसको नहीं आने दिया। उचित और सम्मानपूर्वक संवाद में लेखक सदैव अग्रणी रहा यहाँ तक कि डॉ. नाग और लेखक दोनों में रिटायर होने के पश्चात भी सामजिक मुलाकातें होती रही। इससे दोनों के दिलों में कोई वर्जना तो नहीं रही लेकिन कतिपय सीनियर सदस्यों के दिल नहीं बदल सके।

उपरोक्त वर्णन से यह तो विदित होता है कि विश्वविद्यालय का एक वर्ग डेरी कॉलेज का विरोधी था हालांकि कालान्तर में इंजिनीरिंग के ही एक वरिष्ठ टीचर डेरी कॉलेज के डीन वर्षों तक बने रहे। वे डेरी कॉलेज में कोई एक शैक्षणिक अध्याय नहीं जोड़ सके बल्कि उन के कार्यकाल में डेरी कॉलेज की अनुमोदित पदों की सख्या को सरकार कम करती रही और उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया। दूसरे डीन भी आये जिनमें फिर से एक इंजीनियरिंग के, एक होम साइंस से और एक कृषि संकाय से नियुक्त किये गए जिनकी योग्यता वांछनीय से कोई मेल नहीं खाती थी। सरकार ने कभी भी कुलपति से यह नहीं पूंछा कि डीन की अनिवार्य योग्यताओं को बदलने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, क्या और कोई विकल्प नही मिल सकता था?

इतना ही नहीं अवांछित योग्यता के लोगों को डेरी विज्ञान का डीन नियुक्त करना कुलपतिओं के लिए एक मनोरंजन का साध्य बन गया क्योंकि जहाँ वांछित योग्यता नहीं थी वहां कुलपतिओं ने किसी स्वार्थवश वांछित योग्यता को ही बदल डाला और प्रबंधमंडल से अनुमोदित करा लिया। इससे जिनको प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर कतिपय को और ऊपर बढ़ने के लिए एक सीढ़ी भी मिल सकी।

इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार में बैठे सम्बंधित सचिवों की भूमिका भी संदिग्ध बनी रही। लेखक ने यह भलीभांति अनुभव किया जब उसने जयपुर सचिवालय में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए विदेशी अनुदान और उसकी कंसल्टेटिव समिति द्वारा दी गई विस्तृत रिपोर्ट पर फाइनल चर्चा में भाग लिया। इस समिति को चेयर कर रहे थे एक अतिवरिष्ठ प्रशासन सचिव। मीटिंग में चर्चा के दौरान यह सहमति भी एकमत से बनीं कि प्रदेश में इस अनुदान से संपन्न हुए कार्य संतोषजनक रहे, इस अनुशंसा के साथ विदेशी सदस्यों की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई।

चेयरमैन ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मीटिंग समाप्त कर दी और सदस्य खड़े होकर विसर्जन करने लगे। आश्चर्य से उसी समय चेयरमैन ने मुझे देख कटाक्ष किया कि उदयपुर का डेरी कॉलेज बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां के छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही। मैं भी चूँकि चलने के लिए खड़ा हो चुका था चेयरमैन का चलते हुए कटाक्ष करना मुझे आश्चर्यजनक और हैरानी वाला लगा, बिना समय गवाए तुरंत ही मैनें कहा–"सर, मीटिंग समाप्त हो गई अथवा अभी चालू है?" उनके यह कहने पर कि मीटिंग तो ख़त्म हो चुकी। तब मैनें कहा कि सर इस रिपोर्ट में छात्रों को मिले रोजगार के जो आंकड़े दर्ज हैं वे केवल और केवल मेरे डेरी कॉलेज के हैं जिन्हे सम्पूर्ण विश्व विद्यालय के लिए दर्शाया गया है। वास्तव में डेरी कॉलेज के अलावा अन्य कोई कॉलेज इस तरह के आंकड़े अपने छात्रों के लिए एकत्रित नहीं करता।

इस प्रकरण से मेरी वो भावना सुद्रण हुई जो मैनें संगठित तरीके से भिन्न-भिन्न जगहों से डेरी कॉलेज के विरोध में चलाया गया अदृश्य प्रोग्राम महसूस किया था। मुझे तनिक भी अब (रिटायरमेंट के बाद) शंसय और हिचकचाहट नहीं है कि वो विरोधी तत्व अभी तक सक्रीय बने हुए हैं जिससे डेरी कॉलेज बद से बदत्तर होते हुए भी किन्ही देवीय कारणों से स्थिर बना हुआ है बिना किसी आगे विकास किये।

इस बात को यहाँ प्रचारित करने का मेरा उद्देश्य एक अलग ही है और वह है छात्र वर्ग को दशकों से निरंतर धोखा, झूंठे और मनगढंत सूचनाएँ प्रकाशित करा कर, चार वर्ष का उनका अमूल्य समय और उनके माता-पिता का घोर परिश्रम से पैदा किया धन जो वे अपने पुत्र अथवा पुत्री पर व्यय करते हैं का दुरूपयोग। क्या कोई उपाय है इसे रोकने का? और जो नुकसान समय और धन का हो चुका उसकी भरपाई अथवा पाटनें का? प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि हम ऐसी शासन व्यवस्था में जी रहे हैं जहाँ कोई जवाब देहि नहीं, कितना ही नुक्सान कर दीजिए सरकारी धन का और स्टेकहोल्डर के समय और धन दोनों का।

डेरी कॉलेज में अनियमिताओं के बारे में समय समय पर प्रकाशित खबरों से अखवार भरे पड़े हैं ,कोई देखने वाला नहीं, भले ही वो भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो हो अथवा राज्य की "पब्लिक एकाउंट्स समिति" ही हो अथवा कोई अन्य। सभी बेफिक्र और मूक, कोई हलचल तक नहीं। अंत में मेरी हार्दिक कामना है कि डेरी कॉलेज उदयपुर में छात्र स्नातक शिक्षा के लिए प्रवेश न लें, कहीं अन्यंत्र शिक्षा ग्रहण करें जो उनके भविष्य के लिए कई विकल्प खोलनें में सक्षम होगी।

-प्रो. (सेवानिवृत) वीर बहादुर सिंह,
पूर्व डीन, डेरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय,
(महाराण प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि) उदयपुर।

डमी स्कूल और कोचिंग का घातक गठजोड़: भारतीय शिक्षा प्रणाली का गहराता प्रदूषण

गठजोड़ में तीन मुख्य खिलाड़ी हैं : कोचिंग माफिया, स्कूल प्रबंधन और नौकरशाही

प्रो. अशोक कुमार

भारतीय शिक्षा व्यवस्था आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहां ज्ञानार्जन का मार्ग धुंधला होता जा रहा है और सफलता का एक कृत्रिम बाजार फल-फूल रहा है। हाल ही में समाचार पत्रों में उजागर हुई 'डमी स्कूल' और कोचिंग संस्थानों के बीच की साठगांठ ने उस कड़वी सच्चाई को फिर से सतह पर ला दिया है! राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर देश के अन्य शैक्षिणक केंद्रों तक, 'डमी मॉडल' एक ऐसी संक्रामक बीमारी की तरह फैल चुका है जो हमारी औपचारिक स्कूली शिक्षा की नींव को खोखला कर रहा है।

'डमी स्कूल' का सीधा अर्थ है- एक ऐसा विद्यालय जहां छात्र का नामांकन तो है, लेकिन उसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। छात्र अपना पूरा समय निजी कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बिताता है, जबकि स्कूल प्रबंधन भारी भरकम फीस लेकर कागजों पर उसकी 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कर देता है। यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक व्यापक संस्थागत भ्रष्टाचार है।

इस गठजोड़ में तीन मुख्य खिलाड़ी हैं: कोचिंग माफिया, स्कूल प्रबंधन और नौकरशाही। कोचिंग संस्थान छात्रों को पैकेज बेचते हैं जिसमें स्कूल का डमी एडमिशन भी शामिल होता है। स्कूल बिना पढ़ाए मोटी रकम कमाते हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी मौन सहमति से इस अवैध कारोबार को संरक्षण देते हैं। यह विडंबना ही है कि जहां स्कूलों की कक्षाएं खाली पड़ी हैं, वहीं कोचिंग संस्थान खचाखच भरे हैं।

शिक्षा कभी एक पवित्र संस्कार और साधना थी, लेकिन आज यह पूरी तरह से कमोडिटी (वस्तु) बन चुकी है। जब हम शिक्षा के बाजारीकरण की बात करते हैं, तो हम उस नैतिक पतन की ओर इशारा करते हैं जिसे मैं "एजुकेशन पॉल्यूशन - शिक्षा प्रदूषण" कहता हूँ। यह प्रदूषण केवल पर्यावरण में नहीं, बल्कि हमारी सोच और व्यवस्था में भी घर कर गया है।

एक प्राणि विज्ञानी के दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी जीव के सर्वांगीण विकास के लिए उसका प्राकृतिक परिवेश अनिवार्य होता है। छात्र के लिए स्कूल वह प्राकृतिक परिवेश है जहां वह केवल विषय नहीं सीखता, बल्कि सामाजिक संवाद, खेल, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सीखता है। डमी मॉडल उसे इस परिवेश से काटकर एक कृत्रिम प्रेशर कुकर (कोचिंग) में डाल देता है। परिणाम स्वरूप, हमें रैंक होल्डर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन संवेदनशील और जागरूक नागरिक खो रहे हैं।

आज तक की लगभग सभी सरकारी योजनाएं और नियम इस डमी कल्चर को रोकने में विफल रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी नीतियां केवल सतही लक्षणों का इलाज करती हैं, मूल बीमारी का नहीं। बायोमेट्रिक उपस्थिति या औचक निरीक्षण जैसे उपाय केवल कागजी साबित हुए हैं क्योंकि निरीक्षण करने वाले हाथ भी उसी भ्रष्टाचार की गंगा में धुले हुए हैं। राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही अक्सर इन संस्थानों के रसूख और चंदे के आगे नतमस्तक रहते हैं। जब तक शिक्षा का उद्देश्य केवल वोट बैंक और आंकड़ों का खेल रहेगा, तब तक वास्तविक सुधार की उम्मीद बेमानी है।

इस समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान प्रवेश परीक्षा प्रणाली को जड़ से बदलना है। वर्तमान में, 12वीं की बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच का गैप ही कोचिंग और डमी स्कूलों की जननी है। जब तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का आधार केवल एक दिन की 3 घंटे की परीक्षा रहेगी, तब तक छात्र स्कूल जाने को समय की बर्बादी मानते रहेंगे।

हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जहां निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए! छात्र के 11वीं और 12वीं के शैक्षिणक रिकॉर्ड को प्रवेश का मुख्य आधार बनाया जाए। बोर्ड और एंट्रेंस का एकीकरण होना चाहिए! स्कूल के पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर में जो भारी अंतर है, उसे खत्म किया जाए। रटने की क्षमता के बजाय छात्र की स्वाभाविक योग्यता और रुचि का परीक्षण होना चाहिए।

नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप से ऊपर उठकर अब समय आ गया है कि एक संवैधानिक रूप से स्वतंत्र भारतीय शिक्षा नियामक का गठन किया जाए। यह नियामक चुनाव आयोग या सीएजी की तरह स्वायत्त होना चाहिए।

इस नियामक के पास सख्त ऑडिटिंग, स्कूलों की भौतिक उपस्थिति और आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक डेटा का सीधा नियंत्रण, डमी नामांकन पाए जाने पर बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्कूल की मान्यता और कोचिंग के पंजीकरण को तुरंत रद्द करने का अधिकार। कोचिंग संस्थानों द्वारा किए जाने वाले भ्रामक विज्ञापनों और अनियंत्रित फीस वसूली पर कानूनी लगाम लगाना।: शिक्षा क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक स्वतंत्र विजिलेंस विंग के लिए शक्तियां होनी चाहिए।

डमी मॉडल का सबसे भयावह पहलू छात्रों का गिरता मानसिक स्वास्थ्य है। स्कूल और कोचिंग के बीच संतुलन न बन पाने से छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है, जो अंततः उन्हें आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदमों की ओर धकेलता है। एक छात्र जो स्कूल नहीं जाता, वह एकाकीपन का शिकार हो जाता है। वह केवल फॉर्मूले और शॉर्टकट्स के बीच फंस कर रह जाता है।

शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका कमाना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाना है। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस एजुकेशन पॉल्यूशन से नहीं बचा पाए, तो हम केवल डिग्रियां बांटने वाला कारखाना बनकर रह जाएंगे। डमी स्कूलों और कोचिंग माफिया का यह गठजोड़ राष्ट्र के बौद्धिक भविष्य के लिए एक कैंसर है।

इसके लिए केवल कड़े कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि एक प्रशासनिक इच्छाशक्ति और संवैधानिक स्वायत्तता वाले नियामक की आवश्यकता है। साथ ही, अभिभावकों को भी यह समझना होगा कि उनके बच्चे की रैंक उसके व्यक्तित्व से बड़ी नहीं है।

समय आ गया है कि हम 'शिक्षा बचाओ' को एक जन-आंदोलन का रूप दें, ताकि हमारा शिक्षा तंत्र फिर से ज्ञान, चरित्र और मानवता का प्रकाश फैला सके। जैसा कि मैंने हमेशा माना है-जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक ज्ञान का वृक्ष फलदायी नहीं हो सकता। डमी मॉडल उन जड़ों को काट रहा है, जिसे रोकना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

-प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय

राशिफल

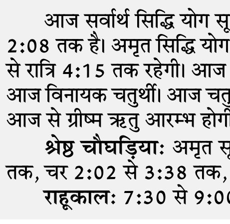

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 20 अप्रैल, 2026

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2083, रोहिणी नक्षत्र रात्रि 2:03 तक, सौभाग्य योग सायं 4:11 तक, गर करण प्रातः 7:28 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। रवियोग रात्रि 2:08 तक है। अमृत सिद्धि योग रात्रि 2:08 से आरम्भ होगा। भद्रा सायं 5:51 से रात्रि 4:15 तक रहेगी। आज सायन वृष में सूर्य प्रवेश प्रातः 7:09 पर होगा। आज विनायक चतुर्थी। आज चतुरथी तिथि का क्षय हुआ है। आज रोहिणी व्रत है। आज से ग्रीष्म ऋतु आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:38 तक, शुभ 9:14 से 10:50 तक, चर 2:02 से 3:38 तक, लाभ-अमृत 3:38 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:02, सूर्यास्त 6:49

मेष

आज आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

वृष

व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आज मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

मिथुन
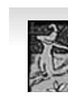
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

कर्क

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आज परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला
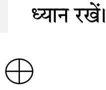
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

मकर

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।